

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1996/2011/अजमेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-बांसवाड़ा।

.....अपीलार्थी।

बनाम्

मैसर्स प्रभात यार्न ट्रेडर्स, किशनगढ़।

.....प्रत्यर्थी।

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से।

श्री दिनेश कुमार,
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक :29.04.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी स्वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बांसवाड़ा (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जो अपील संख्या 177/2009-10/वैट/किशनगढ़ के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "विक्रय कर अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(5) व धारा 58 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) व धारा 55 के तहत आरोपित अनुवर्ती ब्याज रु.1,49,580/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा विक्रय कर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत दिनांक 06.03.1999 को अभियोग दर्ज कर, विक्रय कर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति रु. 69,361/- आरोपित कर, शास्ति आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये आदेश दिनांक 12.02.2002 के प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। उक्त आदेश दिनांक 12.02.2002 के विरुद्ध राजस्व द्वारा कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की समन्वयपीठ द्वारा दिनांक 08.07.2003 को राजस्व की अपील अस्वीकार कर,

लगातार.....2

अपीलीय आदेश दिनांक 12.02.2002 की पुष्टि की गयी। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने रिवीजन संख्या 555/03 स.वा.क.अ, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर बनाम् मै० देव ट्रेडिंग कं० के निर्णय दिनांक 05.09.07 द्वारा उक्त अपील प्रकरण उपायुक्त (अपील्स-चतुर्थ) वाणिज्यिक कर, जयपुर को प्राप्त होने पर, उपायुक्त (अपील्स-चतुर्थ) वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा जरिये आदेश दिनांक 25.02.2009 के प्रकरण को अपीलार्थी सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त पारित आदेश दिनांक 25.02.2009 की पालना में अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने विक्रय कर नियम के नियम 34 के तहत दिनांक 02.09.2009 को आदेश पारित कर, शास्ति रु.69,361/- को पुनर्स्थापित कर, दिनांक 02.09.2009 तक उक्त शास्ति रु. 69,361/- जमा नहीं करवाने के कारण, विक्रय कर अधिनियम की धरा 58 के तहत ब्याज रु. 1,12,110/- व विभाग द्वारा प्रदत्त ब्याज रु.32,630/- एवम् उक्त पर भी ब्याज रु.4,840/- आरोपित कर, आदेश दिनांक 02.09.2009 पारित किया गया। उक्त पारित आदेश दिनांक 02.09.2009 के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर, अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति को यथावत रख, अधिनियम की धारा 58 के तहत निर्धारित कुल ब्याज राशि रु.1,49,580/- को अपास्त कर, आदेश दिनांक 23.02.2011 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

5. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

6. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा विक्रय कर अधिनियम धारा 58 सपठित अधिनियम की धारा 55 के तहत जरिये आदेश दिनांक 02.09.2009 जो ब्याज का आरोपण दिनांक 08.03.1999 से दिनांक 01.09.2009 के लिये आरोपित किया गया है, वह विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति रु.69,361/- की गयी थी वह दिनांक 12.02.2002 से दिनांक 01.09.2009 तक की अवधि के दौरान माननीय न्यायालयों के द्वारा पारित किये गये विभिन्न आदेशों के प्रकाश में

अस्तित्व में ही नहीं थी। कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने रिवीजन संख्या 555/03 स.वा.क.अ, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर बनाम् मै0 देव ट्रेडिंग कं0 के निर्णय दिनांक 05.09.07 के आलोक में, उपायुक्त (अपील्स—चतुर्थ) वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा जरिये आदेश दिनांक 25.02.2009 के मूल शास्ति आदेश दिनांक 08.03.1999 के आरोपित शास्ति को अपास्त कर, प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया था। जिसकी पालना में अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 02.09.2009 के आरोपित शास्ति को पुनर्स्थापित किया गया था। अतः अनुवर्ती ब्याज का आरोपण दिनांक 01.09.2009 तक किसी भी रूप से वसूली योग्य नहीं है। अपने उक्त तर्कों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वा.क.अ. बनाम् राजस्थान टैक्सेशन ट्रिब्यूनल एण्ड अदर्स (2000) 23 टैक्स वर्ल्ड 139, स.वा.क.अ., घट—द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर बनाम् मैसर्स इण्डियन प्लास्टिक वर्क्स,(1999) 15 एस.टी.सी. 104 (आर.टी.टी.), स.वा.क.अ., उड़नदस्ता—द्वितीय, जोधपुर बनाम् मैसर्स मोहन लाल एण्ड कम्पनी, जोधपुर, (2007) 18 टैक्स अपडेट 152 [आर.टी.बी.(एस.बी.)], माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स.वा.क.अ.—घट—तृतीय, बनाम् राजस्थान टैक्सेशन ट्रिब्यूनल व अन्य (2000) 27 आर.टी.जे.एस 84 व कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या—810/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 31.12.2012, अपील संख्या 70/2010/जयपुर निर्णय दिनांक 17.04.2012 को प्रोद्धरित किया। अपने उक्त तर्कों के आलोक में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अपीलीय आदेश दिनांक 23.02.2011 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का निवेदन कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड पत्रावली का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। इस संबंध में निर्णय हेतु विक्रय कर अधिनियम धारा 58 के प्रावधानों का अध्ययन किया गया जिसका मूल पठन इस प्रकार है:—

अधिनियम की धारा 58.— **Interest on failure to pay tax or other sum payable.** — (1) Where a dealer or a person commits a default in making the payment of any amount of tax leviable or payable or

any amount of tax, fee, interest or penalty assessed or determined or of any amount or demand otherwise payable, within the specified time under the provisions of this Act or the rules made or notifications issued thereunder, such dealer or person shall be liable to pay interest on such amount at the rate of two percent per month for the period starting from the day immediately succeeding the date specified for such payment and ending with the day on which such payment is made.

(2) Subject to the provisions of sub-section (2) of section 70, interest under sub-section (1) shall be calculated—

(a) at the time of assessment under any section or in continuation of such assessment; and

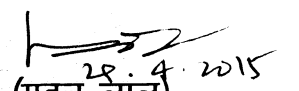
(b) on payment including the adjustment of a demand in full.

(3) The liability to pay interest under the provisions of this section shall also arise for a period which is less than a month.

7. उपर्युक्त वर्णित विधिक प्रावधानों एवम् माननीय न्यायालयों के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, यह पीठ यह अनुभव करती है कि चूंकि अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति जो जरिये आदेश के दिनांक 08.03.1999 को आरोपित की गयी थी, को माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने रिवीजन संख्या 555/03 स.वा.क.अ, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर बनाम् मै0 देव ट्रेडिंग कं0 के निर्णय दिनांक 05.09.07 के आलोक में, उपायुक्त (अपील्स—चतुर्थ) वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा जरिये आदेश दिनांक 25.02.2009 के प्रकरण को अपीलार्थी सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा जरिये आदेश दिनांक 02.09.2009 के पुनर्स्थापित किया गया है। अतः दिनांक 01.09.2009 तक उपर्युक्तानुसार वर्णित शास्ति की मांग राशि अस्तित्व में नहीं होने के कारण वसूली योग्य नहीं थी। अतः विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि ₹.1,49,580/- को अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। फलस्वरूप, अपीलीय आदेश दिनांक 23.02.2011 में हस्तक्षेप करने का विधिक औचित्य नहीं है। अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

8. परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय प्रसारित किया गया।


(मदन लाल)
सदस्य